

financial and commercial aspects of their proposals and evaluate them in comparative terms and submit suitable recommendations for the considerations of Government.

MR. SPEAKER : You do not want to put a supplementary ? No. Shri Laxminarain Pandey.

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे : मंत्री महोदय ने अपने बक्तव्य में कुछ बातें बतलाई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किन फर्मों से छोटी कार बनाने के प्रस्ताव आये हैं ? आप की तरफ से जो कमेटी एप्पाइन्ट हुई थी, उसने किन किन फर्मों के प्रस्तावों के बारे में विचार कर लिया है और इस के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं ?

SHRI MOINUL HAQUE CHOU-DHURY : The offers came from M/s. Fiat of Italy ; M/s. Renault of France ; M/s. Nissan of Japan ; M/s. Ford of Australia ; M/s. Volkswagon of West Germany ; M/s. Zavedi Crvena Zastava of Yugoslavia ; M/s. Toyo Kogyo of Japan and M/s. Alfa Romeo of Italy.

A study Team was appointed in October, 1970 and they submitted a report in October, 1971.

SHRI BANAMALI PATNAIK : What is the final decision of the Government in this regard ?

MR. SPEAKER : I asked you to put a supplementary. But you did not put it.

SHRI BANAMALI PATNAIK : What is the final decision of the Government ?

MR. SPEAKER : You please listen to the. You would like to know the decision of the Government. But the decision of the Speaker should also be heard. You were asked to put your supplementary but kept sitting. So, I called the next member. Now how can allow you to put the supplementary ?

SHRI R.V. SWAMINATHAN : When a similar question was raised in the House

during the last session, the hon. Minister replied that a decision will be taken within a very short period. The impression then given was that within a month or a decision would be taken. Now I want to know how long will the Government take to decide over this matter to select a car ?

SHRI MOINUL HAQUE CHOU-DHURY : The Committee submitted its report in October, 1971. This report was finally considered by the meeting of the Technical and financial Group on 27th October 1971. The matter was submitted to the Government on 1-11-71 and we took it up on the 4th.

SHRI PILOO MODY : Today is 7th November.

SHRI MOINUL HAQUE CHOU-DHURY : We found in the report certain matters which need consideration. Therefore, we have asked for a quick study of these matters and as soon as these matters are studied, the Government will take a decision.

सीमा सुरक्षा बल का एक पृथक सेवा के रूप में पुनर्गठन

*70. डा० संकटा बसाव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल को गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक पृथक सेवा के रूप में पुनर्गठित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने गृह मंत्रालय के उन कर्मचारियों को, जो कि पिछले कई वर्षों से सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में काम कर रहे हैं, इस बारे में अपने विकल्प देने को कहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्वीकृत विस्तृत नियमों तथा विनियमों को कर्मचारियों में परिचालित किया है ;

(घ) क्या सरकार ने सम्बन्धित कर्मचारियों की कोई वरिष्ठता सूची तैयार की है ; और

(ङ) यदि हा, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा किन्तना प्रतिरिक्त व्यय किये जाने की संभावना है ?

यह प्रशासन है राष्‍ट्रप्री : (बी कृष्‍ण च्‍य्‍य क्‍त) : (क) श्रीर (ख). सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय के लिए एक पू्‍यक अनुसन्धित संवर्ग गठित करने का प्रश्‍न सरकार के क्‍षिप्राधीन है। सीमा सुरक्षा बल के गृह-निदेशक ने केन्‍द्रीय सचिवालय सेवा एवं केन्‍द्रीय सचिवालय सेवा में भाग न लेने वाले अन्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्‍त कर्मचारियों की प्रसि-किया जानने की दृष्‍टि से उनसे यह बतलाने के लिए कहा है कि क्या वे इस संवर्ग में, यदि गठित किया गया, प्रवेश करने का विकल्प देना चाहेंगे।

(ग) से (ङ). उपरोक्‍त उत्‍तर (क) को देखते हुए प्रश्‍न नहीं उत्‍त्‍थ।

डा० संकटा प्रसाद : क्या गृह मंत्री बल्लादे की कृपा करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल को गृह मंत्रालय से अलग करने का क्या कारण है ?

श्री कृष्‍णचन्‍द्र पंत : इसका कारण यह है कि अगर बहुत संख्या में ये मिनिस्‍टीरियल काडर के लोग जो उस काडर के नहीं होते और डेपुटेशन पर आते हैं तथा वापिस आते

आते हैं तो उनके वहां को अनुभव प्राप्त होता है वह क्या जाता है और उसकी जरूरत वहां रखी है। इसलिए जो ऐसे संवर्ग है, वेके डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना मिनिस्‍टीरियल काडर है।

Radio Stations for coverage of Tribal Areas

*72. SHRI B K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have set up new Radio stations in the country to provide coverage for the tribal areas;

(b) if so, how many and where ; and

(c) the approximate cost incurred on each station ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SENHA) : (a) to (c). The following new radio stations are being set up and in the existing stations are being strengthened to serve predominantly tribal areas. The approximate cost is shown against each project :—

Radio Stations		Approximate cost (Rs. in lakhs)
Chhatarpur	(new)	51.60
Ambikapur	(new)	72.00
Jagdalpur	(new)	55.20
Rewa	(new)	72.80
Tawang	(new)	10.00
Tezpur	(new)	90.00
Shillong	(expansion of existing station)	73.00
Visakhapatnam	(expansion of existing station)	71.65
Aizal	(expansion of existing station)	54.45
Imphal	(expansion of existing station)	48.00
Kohima	(expansion of existing station)	50.00
Jeypore	(expansion of existing station)	26.98
Total Rs.		675.68